



सितंबर 2024
खंड -07

जलाशय

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

अंक. 2

‘फ्लडवॉच इंडिया’ ऐप

एंड्रॉयड डाउनलोड लिंक -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.affcwc>

iOS डाउनलोड लिंक -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.affcwc>

प्रकाशन

बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़ों पर रिपोर्ट

<https://cwc.gov.in/sites/default/files/report-flood-damage-statistics.pdf>

जलाशय निगरानी

इस महीने में पांच और जलाशय जोड़े गए

<https://cwc.gov.in/en/reservoir-level-storage-bulletin>



Bank revetment using geo bags at Rohmaria, Assam

विषय-सूची

पृष्ठ 1

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें:

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश
लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड
उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड

पृष्ठ 2

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन:

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठ 3

स्थलों/परियोजनाओं का दौरा:

कर्नाटक ऊपरी तुंगा परियोजना, आंध्र प्रदेश के कालबुरगी और यदगीर जिलों की 138 एसएमआई योजनाएं

पृष्ठ 4

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

देश में बाढ़ की स्थिति- अगस्त 2024
संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन

पृष्ठ 5

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति
“फ्लडवॉच इंडिया 2.0” ऐप का शुभारंभ

पृष्ठ 6

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

सतलुज-यमुना लिंक नहर में गतिरोध और वैकल्पिक समाधान
रीसैट-1ए, रीसैट-1बी रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए डेटा का जल संसाधनों में उपयोग के.ज.आ. के निदेशकों के साथ संवादात्मक सत्र

पृष्ठ 7

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)
राज्य स्तरीय सहभागिता बैठक

पृष्ठ 8

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़ों पर रिपोर्ट का प्रकाशन

अध्यक्ष का संदेश



श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

इस स्वतंत्रता दिवस पर, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हम स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाते हैं, आइए हम अपने जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए अपने समर्पण को भी नवीनीकृत करें, जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी को आनंदमय और सार्थक स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।

इस महीने, हमने माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी.आर. पाटिल द्वारा "फ्लडवॉच इंडिया" संस्करण 2.0 के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा इन-हाउस विकसित यह अद्यतन मोबाइल एप्लिकेशन, 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए पहले संस्करण की सफलता पर आधारित है। ऐप अब अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी स्टेशनों को कवर करता है, जिससे कुल संख्या बढ़कर 592 हो गई है, साथ ही उपयोगकर्ताओं को देश भर में बाढ़ की स्थिति का एक

व्यापक और वास्तविक समय का अवलोकन मिलता है। इसके अतिरिक्त, इसमें अब 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति का महत्वपूर्ण डेटा भी शामिल है, जिससे नागरिकों को निचले इलाकों में संभावित बाढ़ के खतरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए रिसैट-1ए, रिसैट-1बी, रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए से उपग्रह डेटा का उपयोग करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद, के.ज.आ.ने विभिन्न डोमेन में उपग्रह डेटा का लाभ उठाने के लिए तीन समर्पित कार्य समूहों का गठन किया है। मेरी अध्यक्षता में, बेहतर जल प्रबंधन के लिए इस मूल्यवान डेटा के उपयोग में प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की छठी और सातवीं बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच रुड़की और के.ज.आ. के अन्य अधिकारी शामिल थे। ये विचार-विमर्श लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों को सुलझाने और समान जल वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के आई एंड जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जहां हमने पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत कार्यान्वित की जा रही कई प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। बांधों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप आपातकालीन कार्य योजना समय पर तैयार करने पर जोर दिया गया।

मुझे "बाढ़ क्षति सांख्यिकी पर रिपोर्ट" जारी करने की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है, जिसमें 1953 से 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से बाढ़ क्षति पर 70 वर्षों से अधिक का डेटा संकलित किया गया है। यह रिपोर्ट बाढ़ की प्रवृत्तियों और बाढ़ से संबंधित नुकसान के आर्थिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिससे भविष्य की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के लिए जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी है।

चूंकि के.ज.आ. के अध्यक्ष के रूप में यह मेरा अंतिम संदेश है, मैं उस टीम और हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी सामूहिक उपलब्धियों में योगदान दिया है। मैं के.ज.आ. के उज्ज्वल भविष्य के विश्वास के साथ और हमने मिलकर जो काम पूरा किया है, उसके लिए गहरी सराहना के साथ यह पद छोड़ रहा हूं। मेरे स्थान पर पद ग्रहण करने वाले अधिकारी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रत्येक नागरिक को समृद्ध और संपन्न भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश



माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2022 के निर्देशों के अनुसरण में संबंधित राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के संबंध में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठकों की श्रृंखला में चौथी बैठक श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित राज्यों के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। पोलावरम परियोजना के पश्चजल प्रभाव के कारण अभिकल्पित बाढ़ और जलमग्नता सहित कई तकनीकी मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पक्षीय राज्यों की प्रमुख चिंताओं को दूर करने और आगे के रास्ते पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया।

बैठक में मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) के साथ-साथ उपनिदेशक, तटबंध(उ.प. और द.), के.ज.आ. ने भाग लिया।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर बन रही लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है के संबंध में के.ज.आ., यूजेवीएनएल और एलएंडटी के अधिकारियों के बीच 30.08.2024 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में

सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस परियोजना का निर्माण यूजेवीएनएल द्वारा किया जा रहा है। यूजेवीएनएल ने अभिकल्पन परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैठक के दौरान, यूजेवीएनएल द्वारा प्रस्तुत शीयरज़ोन उपचार पद्धति, बांध की नींव/एबटमेंट के उत्खनन/पट्टी के चित्र, 3-डी गतिशील विश्लेषण के टीओआर, अपस्ट्रीम कोफ़रडैम, डायवर्जन सुरंग, इनलेट पोर्टल और आउटलेट पोर्टल, बिजली सेवन स्थान और जल कंडक्टर प्रणाली के नए जारी किए गए वैकल्पिक चित्र, पावरहाउस कॉम्प्लेक्स और टेल रेस सिस्टम मुद्दों से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई।

उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 38वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 38वीं बैठक 13.08.2024 को के.ज.आ., नई दिल्ली में सदस्य (ज.आ. एवं प.), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ. मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और वापकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखंड द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वापकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, बिहार भाग (आरडी 68.37 किमी से 09.09 किमी) में आरएमसी और इसकी संरचनाओं के अस्तरण, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा की स्थिति, झारखंड में दाहिनी मुख्य नहर के 12 लघु वितरिका नेटवर्क के मूदा कार्य, मरम्मत और निर्माण के लिए निविदा की स्थिति, बिहार में आरएमसी से वितरण प्रणाली के निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति, आरएमसी से बिजली के खंभों की शिफ्टिंग की स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर चर्चा हुई।

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	भारत में जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन	एक सप्ताह	26	जल संसाधन विभाग और के.ज.आ. के गैर-तकनीकी अधिकारियों के लिए
2	मौजूदा बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन	दो सप्ताह	25	राज्य सरकारों/पीएसयू के अधिकारियों और उन अधिकारियों के लिए जो व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन और संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं।
3	भारत में जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन	एक सप्ताह	22	गैर सरकारी संगठनों, मीडिया पेशेवरों और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों के लिए।
4	जल संसाधन प्रबंधन में गूगल अर्थ इंजन और अनुप्रयोगों का परिचय	दो सप्ताह	55	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत



स्थलों/परियोजनाओं का दौरा

कर्नाटक के कालबुर्गी और यदगीर जिलों की 138 एसएमआई योजनाएं

निदेशक, श्री अशोक कुमार वी द्वारा 27.08.2024 और 28.08.2024 को कालबुर्गी जिले के 4 तालुकों नामतः कलगी, कमलापुर, अफजलपुर और सेदाम और यदगीर जिले के 2 तालुकों नामतः गुरमितकल और वाडेगेरा की पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत 15 एसएमआई योजनाओं का दौरा किया गया। अरुण कुमार, डीडी एवं श्री सुंदरा पी, एडी, मूल्यांकन निदेशालय, एमएसओ, के.ज.आ., बेंगलुरु के साथ अधिशासी अभियंता, सहायक अधिशासी अभियंता और लघु सिंचाई विभाग, कर्नाटक सरकार के संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।



ऊपरी तुंग परियोजना

ऊपरी तुंगा परियोजना(एआईबीपी)का दौरा 30/07/2024 से 01/08/2024 के दौरान डॉ. जे. हर्षा निदेशक(निगरानी) और श्री ए मणि मारन, उप निदेशक (निगरानी), प्रबोधन दक्षिण संगठन, के.ज.आ., बेंगलुरु द्वारा किया गया है।



I. बाढ़ से सम्बंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति - अगस्त 2024

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2024 से शुरू हुई। 1 मई से 31 अगस्त 2024 की अवधि के दौरान, कुल 6752 (4971 स्तर + 1781 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए और 6390 (4735 स्तर + 1655 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 94.63% प्रतिशत सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से अगस्त 2024 माह के दौरान 134 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 124 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2024 से 31.08.2024 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ स्थिति

चार बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	असम	जोरहाट	ब्रह्मपुत्र	नेमतिघाट	30/06/2024	02/07/2024
2		सोनितपुर	जिया-भराली	एनटी रोड क्रॉसिंग	01/07/2024	01/07/2024
3		शिवसागर	दिखो	शिवसागर	02/07/2024	02/07/2024
4		डिब्रूगढ़	बुरिदेहिंग	खोवांग	02/07/2024	03/07/2024

35 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 72 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा,

संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन



गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, झारखंड और तेलंगाना में 102 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक और गुजरात के 45 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 68 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ।



केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 2023 में 22 अगस्त, 2024 को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए समिति की चौथी बैठक की। बैठक में के.ज.आ., जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब और उत्तराखंड, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, एनआरएससी, एनडब्ल्यूआईसी, एसजेवीएनएल,

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

एचपीपीसीएल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एसडीएमए, हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग आदि के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि समिति की मसौदा रिपोर्ट बैठक से काफी पहले ही परिचालित कर दी गई थी। समिति की प्रगति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए, अध्यक्ष ने

समिति के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए टीम की सराहना की।

बैठक में विचार-विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों ने मसौदा रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की और इसकी सामग्री पर गहन चर्चा की। रिपोर्ट की स्पष्टता बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। कुछ समायोजन करने के बाद, रिपोर्ट के अंतिम संस्करण को समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

II. अंतर्राज्यीय विवाद

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति



पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की छठी और सातवीं बैठकें क्रमशः 8 और 29 अगस्त 2024 को के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। दोनों बैठकों में कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, एनआईएच रूड़की के प्रतिनिधियों और केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें पेन्नैयार नदी पर 1892 और 1933 के समझौतों की प्रयोज्यता, तमिलनाडु द्वारा उठाई गई परियोजनाएं, भूजल की स्थिति और पानी की गुणवत्ता शामिल हैं। वार्षिक प्रकृत अपवाह के आकलन के लिए कर्नाटक से अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता पर बल दिया गया। सातवीं बैठक के दौरान, ड्राफ्ट रिपोर्ट (भाग-1) और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन की समीक्षा की गई और सभी सदस्यों द्वारा आवश्यक संशोधनों पर सहमति व्यक्त की गई। अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु को अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था।

III. अन्य गतिविधियाँ

"फ्लड वॉच इंडिया" 2.0 ऐप का प्रमोचन

भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने 13.08.2024 को सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और जलशक्ति मंत्रालय एवं के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में "फ्लड वॉच इंडिया" मोबाइल एप्लिकेशन के दूसरे संस्करण का प्रमोचन किया।

पहले वाले संस्करण में 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान की जाती थी। ऐप का संस्करण 2.0 अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर वर्तमान जानकारी प्रदान करता है, जिससे स्टेशनों की कुल संख्या 592 हो गई है।

नवीनतम संस्करण देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है।



उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप अंग्रेजी और हिंदी में सभी जानकारी प्रस्तुत करता है और पठनीय और ऑडियो प्रसारण प्रारूप में उपलब्ध है। ऐप निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

'फ्लड वॉच इंडिया' ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपकरणों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को व्यापक अभिगम्यता प्रदान करता है।

एंड्रॉइड डाउनलोड लिंक-

<https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.affcwc>

iOS डाउनलोड लिंक-

<https://apps.apple.com/in/app/floodwatch-india/id6478849444>

सतलुज-यमुना लिंक नहर में गतिरोध पर बैठक और सिंधु जलसंधि के परिप्रेक्ष्य से वैकल्पिक समाधान

सतलुज-यमुना लिंक नहर में गतिरोध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सिंधु जल संधि के परिप्रेक्ष्य से वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नई दिल्ली में भारत सरकार के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी।

उपरोक्त बैठक की तैयारी हेतु मंत्रालय की तैयारियों और स्थिति का आकलन करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (जल संसाधन विभाग) के सचिव की अध्यक्षता में 16 अगस्त 2024 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., मुख्य अभियंता (डिजाइन, एन एंड डब्ल्यू) और के.ज.आ. तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, निदेशक, आईएसएम, के.ज.आ. द्वारा एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों से पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मुद्दों और विभिन्न वैकल्पिक समाधानों की रूपरेखा दी गई।

जल संसाधनों में रिसैट-1ए, रिसैट-1बी रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए डेटा का उपयोग

जल संसाधनों में रिसैट-1ए, रिसैट-1बी रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए डेटा के उपयोग की प्रगति हेतु की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 09.08.2024 को सेवा भवन, नई दिल्ली में अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में बैठक आयोजित की गई थी।

जल संसाधनों रिसैट-1ए, रिसैट-1बी रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए से उपग्रह डेटा के उपयोग के

लिए जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर (जल शक्ति मंत्रालय) और अंतरिक्ष विभाग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की मंजूरी के साथ, के.ज.आ. ने 19 जनवरी, 2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह डेटा के उपयोग के लिए तीन कार्य समूहों का गठन किया है, जो इस प्रकार हैं:

1. बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन के लिए कार्य समूह ए
 2. जल संसाधन योजना के लिए कार्य समूह बी
 3. मानचित्रण संबंधी गतिविधियों के लिए कार्य समूह सी
- के.ज.आ. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को आयोजित अनुवर्ती समीक्षा बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (जलशक्ति मंत्रालय) के आदेश के अनुसार उपग्रहों रिसैट-1ए, रिसैट-1बी रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए से डेटा के उपयोग का मूल्यांकन किया गया। बैठक में कार्य समूह ए, बी और सी द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें जल संसाधन विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) में विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह डेटा के अनुप्रयोग की निगरानी और बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और भविष्य की कार्रवाइयों के लिए दिशा निर्धारित करने में ये चर्चाएँ महत्वपूर्ण रहीं।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने आकृति विज्ञान, हिमनदी झीलों, फसल क्षेत्र अनुमान, जल निकाय स्तर अनुमान, बाढ़ से घिरे क्षेत्रों और ऊंचाई आदि जैसे क्षेत्रों पर अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

के.ज.आ. के निदेशकों के साथ संवाद सत्र



श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 12.08.2024 को मुख्यालय/फील्ड कार्यालयों में तैनात के.ज.आ. के सभी निदेशकों/अधीक्षक इंजीनियरों (एसई) के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। बातचीत के दौरान, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अधिकारियों को के.ज.आ. की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने और उन्नत करने के लिए उनके कार्य अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया।

अधिकारियों ने संगठनात्मक जरूरतों जैसे बुनियादी

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

ढांचे और जनशक्ति, प्रारूपण/नोटिंग की तैयारी में सुधार, बजट आवंटन, उद्यम के नए क्षेत्र, आउटसोर्स सेवाओं और निविदा प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियाँ, मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयों के बीच तालमेल बनाए रखना, वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन, प्रशासनिक मुद्दे, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के समय अन्य आवश्यकताओं आदि जैसे व्यापक विषयों पर बात की। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने प्रतिभागियों को उपरोक्त मामलों के संबंध में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों के करियर की प्रगति, पदोन्नति, कैडरसमीक्षा, क्षमता निर्माण, शक्तियों का प्रत्यायोजन, सॉफ्टवेयर के उन्नयन, नवीनतम और आगामी प्रकाशनों को जारी करने और के.ज.आ. के भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव बहुत उपयोगी हैं और के.ज.आ. के कामकाज में और सुधार लाने में मदद करेंगे।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की 78वीं बैठक



राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की 78वीं बैठक 8 अगस्त, 2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ., मुख्य अभियंता (एचएसओ), के.ज.आ., निदेशक, एनआईएच; बैठक में आईआईटी-धारवाड़, आईआईटी-रुड़की, आईआरआरआई, एमएनआईटी, जयपुर, आईआईटी-गुवाहाटी और संभागीय और क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुखों अन्य समिति के सदस्यों और एनआईएच के वैज्ञानिकों के सदस्यों ने भी भाग लिया।

समिति ने संस्थान के तकनीकी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वर्ष 2023-24 के लिए पूरे हो चुके कार्य एवं वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित कार्य की समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों ने इस संबंध में उपयोगी सुझाव दिये।

अध्यक्ष ने संस्थान के तकनीकी कार्यों पर विभिन्न सुझाव

भी दिए और इच्छा जताई कि अन्य संस्थानों के साथ और अधिक सहयोगी परियोजनाएं चलायी जानी चाहिए।

हिमनद झील जोखिम अनुक्रमण



केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 22 अगस्त 2024 को ग्लेशियल झील जोखिम सूचकांक पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए दूसरी बैठक की।

एनडीएमए, एनडीएसए, एनआरएससी, आईएमडी, सी-डैक, जीएसआई, डीजीआरई, एनआईएच, सीईए, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस के अधिकारियों और के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान विचार हेतु प्रस्तावित 13 मापदंडों पर सहमति बनी। जोखिम अनुक्रमण के लिए प्रस्तावित ढांचे की सभी ने सराहना की और पाया कि इससे जीएलओएफ के प्रभावों को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तृत अध्ययन के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिमनद झीलों को प्राथमिकता देने में बहुत मदद मिलेगी। प्रस्तावित दस्तावेज़ विभिन्न एजेंसियों द्वारा जोखिम अनुक्रमण को मानकीकृत करने में मदद करेगा।

राज्य स्तरीय संवाद बैठक

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी और जीएफसीसी के अधिकारियों की टीम के साथ 16 अगस्त 2024 को लखनऊ में आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बातचीत की।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने यूपी राज्य में के.ज.आ. की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश में बाढ़ की स्थिति के साथ-साथ देश में महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए के.ज.आ. द्वारा इन-हाउस विकसित एक मोबाइल ऐप "फ्लडवॉच" के हाल ही में लॉन्च किए गए उन्नत संस्करण का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने यूपी में ई-फ्लो मॉनिटरिंग के संबंध में डेटा नियमित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राज्य के अधिकारियों को के.ज.आ. द्वारा जारी हालिया तकनीकी

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ



प्रकाशनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई जो राज्य में जल संसाधन योजना में उपयोगी होंगे।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और मूल्यांकन एवं डिजाइन परामर्श के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सभी निर्दिष्ट बांधों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आपातकालीन कार्य योजना की शीघ्र तैयारी पर भी जोर दिया गया। सभी निर्दिष्ट बांधों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आपातकालीन कार्य योजना की शीघ्र तैयारी पर भी जोर दिया गया। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने आई एंड डब्ल्यूआरडी अधिकारियों से आईआईटी-रुड़की और आईआईएससी, बेंगलुरु में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में एम-टेक पाठ्यक्रमों में अधिक अधिकारियों को नामित करने और एनडब्ल्यूए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए कहा।

आई एंड डब्ल्यूआरडी, यूपी ने भी विभिन्न मुद्दों पर एक प्रस्तुति दी और के.ज.आ. से मार्गदर्शन मांगा। विचार-विमर्श किया गया और इन मुद्दों से निपटने के लिए उपयोगी सुझाव सामने आए।

प्रमुख सचिव, सूचना एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तरीय बातचीत के लिए के.ज.आ. द्वारा की गई पहल की सराहना की।

बाढ़ क्षति सांख्यिकी पर रिपोर्ट का प्रकाशन

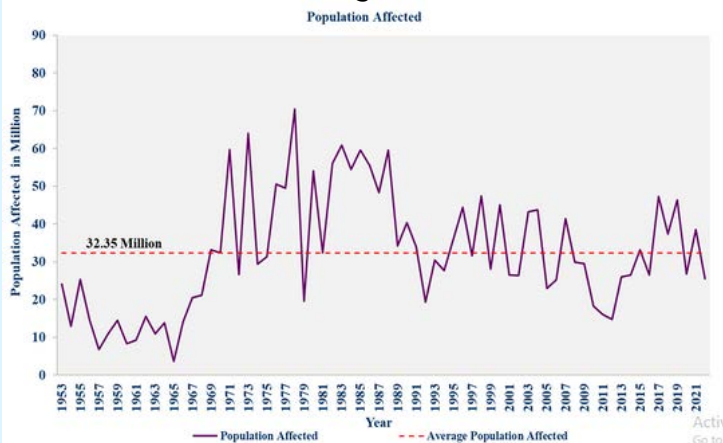
केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने केंद्रीय



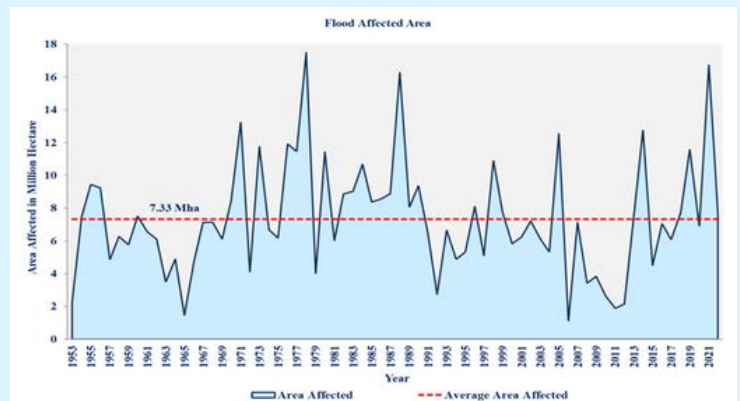
जल आयोग द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन "बाढ़ क्षति सांख्यिकी पर रिपोर्ट" को जारी किया। यह कार्यक्रम सदस्य आरएम, के.ज.आ., सदस्य, डब्ल्यूपीएंडपी, के.ज.आ. और के.ज.आ. (मुख्यालय और फील्ड फॉर्मेशन) के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री वोहरा ने कहा कि दीर्घकालिक आंकड़ों के संकलन का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में तर्कसंगत निर्णय लेना है। के.ज.आ. ने 1953 से 2022 तक भारत के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बाढ़ क्षति एकीकृत डेटाबैंक को संकलित किया है। वर्तमान रिपोर्ट में बाढ़ से होने वाले नुकसान की प्रवृत्ति और मौद्रिक नुकसान के प्रतिशत का निरीक्षण करने के लिए आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। रिपोर्ट में 1953-2022 के दौरान बाढ़ के कारण प्रभावित आबादी, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित फसल क्षेत्र, क्षतिग्रस्त घरों की संख्या, मानव और मवेशियों के जीवन की हानि की मात्रा और क्षति की कुल लागत के संबंध में क्षति की सीमा को शामिल किया गया है। रिपोर्ट का पीडीएफ संस्करण के.ज.आ. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लिंक-

<https://cwc.gov.in/sites/default/files/report-flood-damage-statistics.pdf>



बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या (1953-2022)



बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र (1953-2022)

जलाशय निगरानी

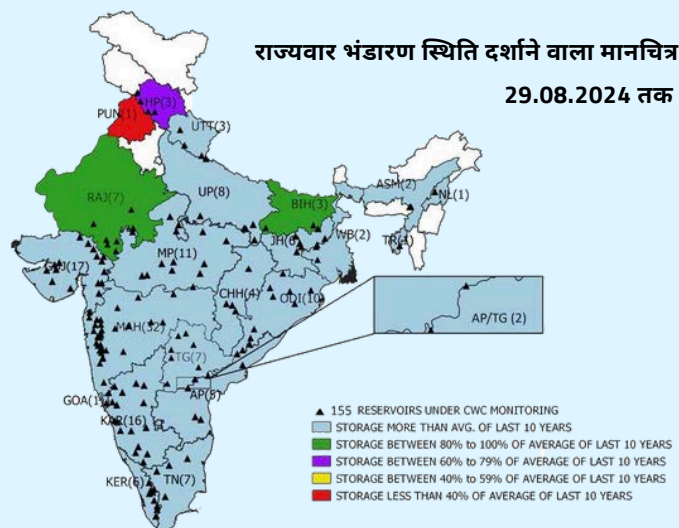
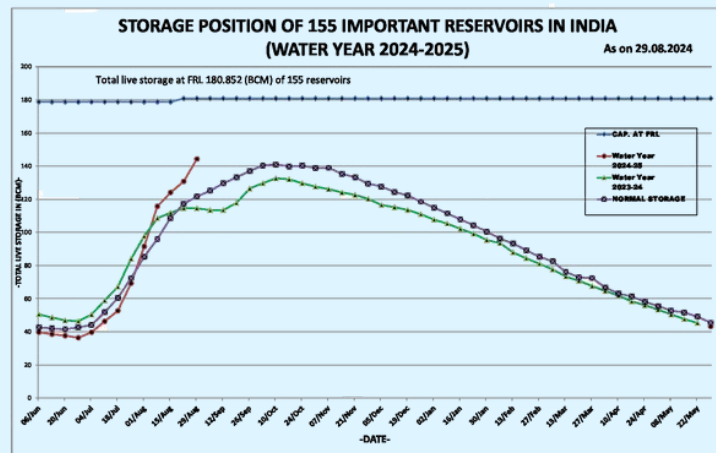
के.ज.आ.के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली(आरएसएमएस)में अगस्त 2024 के महीने में निम्नलिखित पांच और जलाशय जोड़े गए हैं।

जलाशय का नाम	राज्य	सक्रिय भंडारण क्षमता
सोम कमला अम्बा	राजस्थान	0.173
बदुआ बांध	बिहार	0.11
दुर्गावती	बिहार	0.26
सलाउलिम	गोवा	0.227
पुलिचिंतला	आंध्र प्रदेश	1.300
	कुल=	2.070

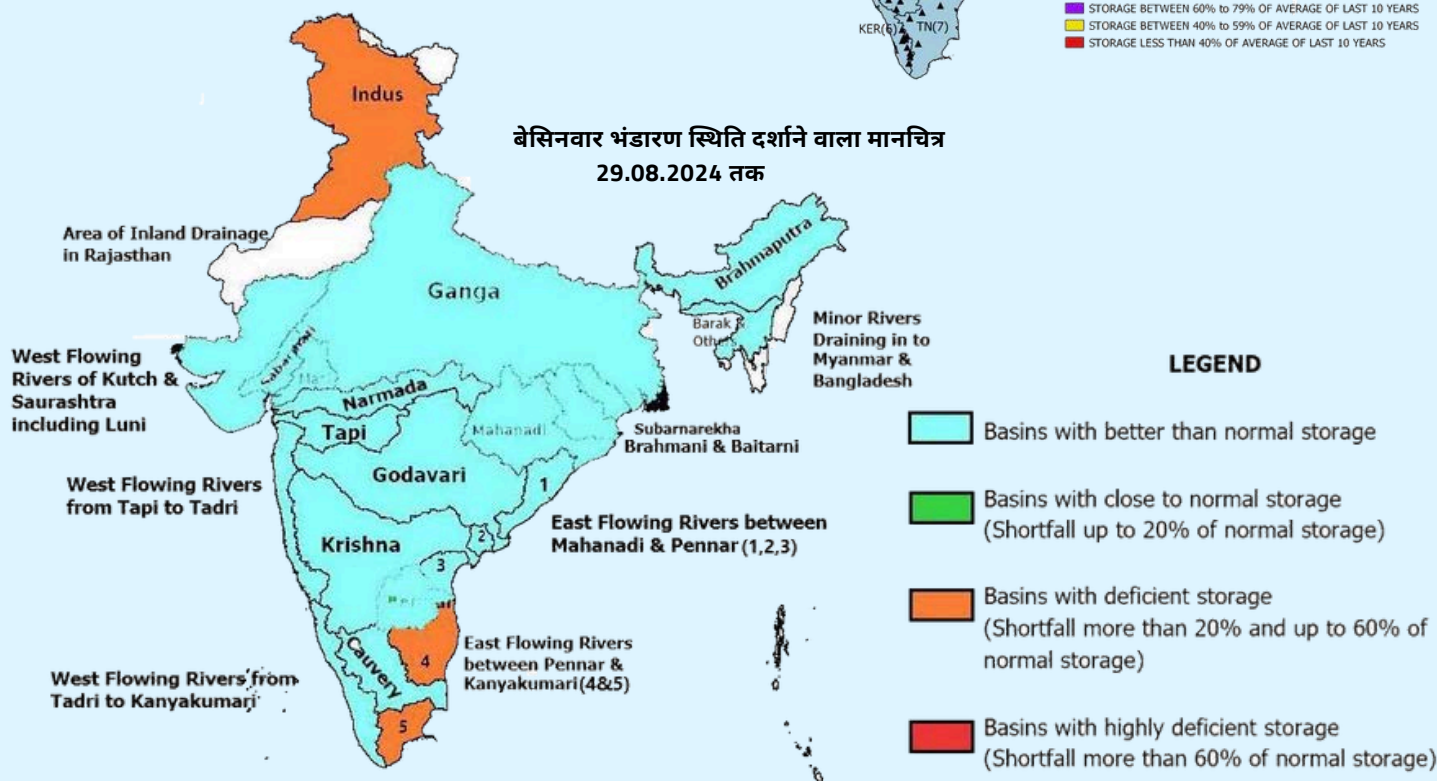
अब, के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 155 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 155 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 70.15% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.08.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 144.333 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 80% है। हालाँकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए

इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 114.543 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत भंडारण 121.619 बीसीएम था। इस प्रकार, 29.08.2024 बुलेटिन के अनुसार 155 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 126% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 119% है।



बेसिनवार भंडारण स्थिति दर्शाने वाला मानचित्र
29.08.2024 तक



दीर्घा



यमुना बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद के नेतृत्व में संग्रहालय एवं प्रदर्शनी उपमंडल, नई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस 29.08.2024 के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोदय कन्या विद्यालय पुष्प विहार, नई दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग कंपटीशन आयोजित कराया गया एवं उन्हें जल बचत व इसकी महत्ता के बारे सूचित एवं प्रेरित किया गया।

स्वतंत्रता दिवस 2024



राष्ट्रीय अन्तरिक्ष दिवस 2024



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री भूपिंदर सिंह, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता (पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. गंगवार, निदेशक (टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक (डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री श्री शोखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री रवि रंजन, निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केंद्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

